

सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 14

22 जुलाई से 5 अगस्त 2026

मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष

कुल पृष्ठ : 8

मूल्य : 4 रुपये पृष्ठ 1

महान फ्रेडरिक एंगेल्स जिन्दाबाद



28 नवंबर 1820—5 अगस्त 1895

“जब एक व्यक्ति दूसरे को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाता है, जिससे मौत हो जाती है, तो हम

इस करतूत को मानव-हत्या कहते हैं; जब मारने वाले को पहले से पता था कि चोट घातक होगी, तो हम उसकी इस करतूत को हत्या कहते हैं। लेकिन जब समाज सैकड़ों सर्वहाराओं को ऐसी स्थिति में रखता है कि वे अनिवार्य रूप से एक बहुत असामयिक और एक अप्राकृतिक मौत को प्राप्त करते हैं, जो कि हिंसा से हुई वैसी ही मौत है, जैसी कि तलवार या गोली से हुई मौत; जब यह जीवन की हजारों आवश्यकताओं से वंचित करता है, उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रखता है, जिनमें वे रह नहीं सकते—उन्हें कानून के मजबूत हाथों से ऐसी परिस्थितियों में तब तक रहने के लिए मजबूर करता है, जब तक कि उनकी मौत

नहीं हो जाती, जो कि अपरिहार्य परिणाम है—जानता है कि इन हजारों पीड़ितों का नाश होना तय है, और फिर भी इन परिस्थितियों को बने रहने देता है, यह करतूत निश्चित रूप से एक वैसी ही मौत है, जैसी कि एक व्यक्ति की करतूत के रूप में; प्रछन्न, द्वेषपूर्ण हत्या, जिससे कोई अपना बचाव नहीं कर सकता, जो प्रतीत नहीं होती कि क्या है, क्योंकि हत्यारे को कोई मनुष्य नहीं देखता, क्योंकि पीड़ित की मौत स्वाभाविक-सी लगती है, चूंकि अपराध जानलेवा जुर्म करने के बजाय भूल-चूक अधिक है। लेकिन हत्या तो हत्या है।...” (इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग की दशा, 1845.)

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी

अयोध्या के राम मंदिर से बड़ी मात्रा में चढ़ावे और दान की चोरी को लेकर जब देश में हंगामा मचा हुआ है और विश्व हिन्दू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभावशाली नेताओं और कार्यकर्ताओं की इसमें संलिप्तता की आलोचना हो रही है, ऐसे में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले इस संगठित चोरी को “दुर्भाग्यपूर्ण” और “अपवाद” बताते हुए स्थिति को संभालने के लिए मैदान में उतर गये हैं।

दत्तात्रेय ने चोरी की घटना के मुख्य दोषियों और पूरे गैंग को सामने लाने तथा उन्हें कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस जांच की मांग करने की बजाय पूरी घटना को ‘देशविरोधी ताकतों की साजिश’

करार देते हुए हिन्दुओं को एकजुट रहने और सब्र व संयम बरतने की सलाह दी है। देश के लोग पूछ रहे हैं कि दत्तात्रेय किस बात को देशविरोधी ताकतों की साजिश कह रहे हैं—संघ परिवार से जुड़े लोगों द्वारा साल दर साल चढ़ावे के पैसे और अन्य दान की चोरी की घटना को या कि चोरी की घटना को जानकर ऐसी भयंकर घटना की निंदा करते हुए साजिश के मुख्य दोषियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा देने की मांग करने वाले लोगों को? होसबले के बयान से स्पष्ट है कि जिन्होंने इस तरह से भक्तों के चढ़ावे और दान की लूट की, उन्होंने देशविरोधी काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया, जो

➡ (शेष पृष्ठ 2 पर)

आजीवन क्रान्तिकारी कॉमरेड रबिन समाजपति स्मृति सभा

केन्द्रीय कमेटी की श्रद्धांजलि

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य और झारखंड राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने मस्तिष्क रक्तस्राव (ब्रेन हेमरेज) की वजह से पिछले 26 जून 2026 को कोलकाता के नेशनल न्यूरोसाइंस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे 77 साल के थे।

गरीब परिवार की संतान कॉमरेड रबिन समाजपति कोलकाता के चारुचन्द्र कॉलेज में अध्ययन के दौरान छात्र संगठन एआईडीएसओ

के संपर्क में आये। वे इस संगठन के जरिये इस युग के एक प्रमुख अग्रणी मार्क्सवादी चिंतक तथा सर्वहारा वर्ग के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के क्रांतिकारी विचारों से आकर्षित हुए और एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का जीवन अपना लिया। परिवार और माता-पिता की आशा-आकांक्षा—कोई भी बंधन उन्हें पीछे नहीं खींच सका। आपातकाल के दौरान 1976 में महान मानवतावादी साहित्यकार शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय की जन्मशताब्दी मनाने के मौके पर

गठित ‘अखिल बंगाल शरद शतवार्षिकी कमेटी’ के एक संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। शरदचन्द्र के बारे में कॉमरेड शिवदास घोष के विशिष्ट मूल्यांकन को उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश की। 1977 में सीपीआई(एम) द्वारा पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के बाद शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के पक्ष में और पास-फेल प्रथा



समाप्त कर दिये जाने के खिलाफ तथा 1983 में बस भाड़े में बढ़ोतरी के खिलाफ आन्दोलन में कॉमरेड रबिन समाजपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर वे अपने संघर्षों के जरिये एआईडीएसओ के अखिल भारतीय नेता के रूप में

उभरे। 1986 में दिल्ली में आयोजित एआईडीएसओ के अखिल भारतीय सम्मेलन में वे संगठन के महासचिव चुने गये। इसी समय से वे पार्टी की जरूरत से पश्चिम बंगाल के बाहर

➡ (शेष पृष्ठ 5 पर)

नासिरनगर में तोड़फोड़: क्या यह किसी ‘अदृश्य ताकत’ की करतूत है?

सूरत के एक अल्पसंख्यक इलाके नासिरनगर में 29 और 30 मई 2026 को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसमें करीब सौ मकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। चश्मदीनों के मुताबिक, वहां भारी तादाद में पुलिस बल, भाजपा के कब्जे वाली सूरत नगर निगम के कर्मचारी और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) के अधिकारी मौजूद थे। वहां रहने वाले लोग आज भी उन खौफनाक पलों को याद करते हैं, जब औरतें, बच्चे और बुजुर्ग रोते-बिलखते अपने आशियाने और सामान को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और बुलडोजर उनके घरों को रौंदते जा रहे थे।

यह पूरी कार्रवाई कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच की गई। वहां तैनात पुलिसवाले तमाशबीन बने सब

कुछ चुपचाप देखते रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूदगी के पक्के वीडियो और तस्वीरें होने के बावजूद, एसओजी के बड़े अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। वहीं सूरत नगर निगम ने दावा किया कि उनके कर्मचारी सिर्फ जमीन की पैमाइश (नाप-जोख) और सड़क के किनारे की नाप लेने के लिए वहां गए थे। इस तरह, मौके पर मौजूद होने के बाद भी किसी भी महकमे ने इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी नहीं ली। तो क्या हम यह मान लें कि यह बिना किसी कानूनी मंजूरी के की गई तोड़फोड़ थी?

पहला सवाल यह उठता है कि अगर यह कार्रवाई गैर-आधिकारिक थी, तो पूरी तोड़फोड़ के दौरान पुलिस और एसओजी के जवान वहां क्या कर रहे थे? दूसरा, अगर

नगर निगम की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, तो उसके बड़े अधिकारी वहां काम की निगरानी करते हुए क्यों देखे गए? तीसरा, अगर ये मकान गैरकानूनी भी थे, तो वहां रहने वालों को कानूनन कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया और उन्हें किसी दूसरी मुनासिब जगह पर क्यों नहीं बसाया गया? अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, तो इस ‘गैरकानूनी’ हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक संगीन जुर्म का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? इसमें सबसे खास बात यह सामने आई है कि इस काम में नगर निगम के ढांचे से जुड़े ठेकेदारों का हाथ था। आरोप है कि तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल किये गए बुलडोजर उन्हीं लोगों के जरिये किराये पर लाये गए थे, जो नगर निगम में ठेकेदारी करते हैं।

➡ (शेष पृष्ठ 2 पर)

विश्वविद्यालयों के दस्तावेजों से ‘इंडिया’ नाम हटाने के पीछे क्या है मंशा?

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई विश्वविद्यालय छात्रों की डिग्री और मार्कशीटों से ‘इंडिया’ शब्द हटाकर उसकी जगह ‘भारत’ लिख रहे हैं या लिखने की तैयारी कर रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि इंडिया और भारत एक ही देश के नाम हैं। फिर यह बदलाव करने की आखिर क्यों जरूरत महसूस हुई?

मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार वर्मा ने मीडिया से कहा कि जी-20 सम्मेलन में हमारे देश ने ‘भारत’ नाम से भाग लिया था। इसलिए विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने देश का नाम ‘भारत’ करने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी इंडिया शब्द हटा दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति

राकेश सिंहाई ने गर्व के साथ कहा कि सबसे पहले उनके विश्वविद्यालय ने यह परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया शब्द का प्रयोग बंद कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने भी इंडिया की जगह भारत लिखने का निर्णय लिया है। लेकिन इस परिवर्तन का कोई ठोस और तर्कसंगत कारण कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल का कहना है कि इंडिया नाम विदेशियों ने दिया था। लेकिन क्या केवल इसलिए कि यह नाम विदेशियों द्वारा दिया गया था, इसे छोड़ देना चाहिए?

➡ (शेष पृष्ठ 7 पर)

राम मंदिर में ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

इसका विरोध कर रहे हैं। धर्म के प्रति होसबले की कितनी गहरी श्रद्धा है!

हिन्दुत्ववादी होसबले को यह याद रखना चाहिए कि देश में हिन्दू धर्म मानने वाले लोग, जिनकी आस्था और भावनाओं को चोरी की इस घिनौनी घटना ने काफी चोट पहुंचाई है, इस घटना की कड़ी निंदा करेंगे या इस पर सब्र और संयम बरतेंगे, यह उनका अपना मामला है, किसी ने आरएसएस-विश्व हिन्दू परिषद को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी है। हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व एक नहीं हैं। हिन्दुत्व हिन्दू धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर राजनीतिक मकसद हासिल करने का एक साधन है। इन हिन्दुत्ववादियों ने ही आज देश के बड़े-बड़े मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है और उन पर उनका एकछत्र दबदबा कायम है। वहां हिन्दू धर्म के प्रति समर्पित हिन्दू भक्तों की व्यवहारतः कोई भूमिका नहीं है।

चंदे की लूट का यह बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू में काफी समय तक चुप्पी साधे रहे। उन्होंने यह कहकर इसे दबाने की कोशिश की कि इसके पीछे कोई साजिश है। प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे रहे। लेकिन देशभर में बढ़ते शोर-शराबे और कड़ी अलोचनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक सक्रिय होकर पहले तीन सदस्यों वाली स्पेशल एसआईटी (इन्वेस्टिगेशन टीम) बनायी और बाद में एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर हुई। मंदिर के कई आम कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई और आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि इस बात को कौन नहीं समझता है कि मंदिर की स्थापना के समय से ही चल रहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना आला दर्जे की मिलीभगत के नामुमकिन है। इस सवाल का साफ-साफ जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए कि कर्मचारियों के अलावा चोरी का पैसा और किन-किन लोगों को मिला है। यह शक करने के पर्याप्त कारण हैं कि होसबले का बयान इस जांच में रुकावट डालेगा या जांच को लक्ष्मण रेखा पर रोक देगा। क्योंकि भ्रष्टाचार तो सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं हुआ है, हिन्दुओं के पवित्र धाम कहे जाने वाले चार धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर में भी चोरी की घटना सामने आयी है। वहां, भैरव सेना नाम के एक हिन्दुत्ववादी संगठन ने मंदिर में चोरी का आरोप लगाया है। यह आरोप खारिज कर देने वाला नहीं है, यह इस बात से साफ है कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने एक समिति बनाकर इसकी जांच के आदेश दे दिये हैं। हालांकि जब द्विवेदी के करीबी पर ही चोरी में शामिल होने का आरोप है, ऐसे में देश के लोगों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी बनायी समिति कितनी सच्चाई सामने ला पायेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने चोरी के इस आरोप की रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं की। गौरतलब है कि ये हेमंत द्विवेदी भाजपा से ही जुड़े हैं। उन्हें राजनीतिक कनेक्शन के कारण ही मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

अब अचानक प्रधानमंत्री राम मंदिर पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

क्यों? राम मंदिर ट्रस्ट तो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। ट्रस्ट के नौ सदस्य सीधे तौर पर संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। क्या इतने लंबे समय से संघ परिवार के सदस्यों के महान नैतिक चरित्र और गुणों की तारीफ करके जनमानस में प्रधानमंत्री जो धारणा तैयार करते आये हैं, वह सत्य नहीं थी? अब तक आरएसएस भारतीय हिन्दू संस्कृति की जो बात करता आया है, यह दावा करता आया है कि चरित्र गठन ही उसकी विचारधारा की मूल भावना है, क्या उनके आचरण से यह मेल खाता है? ट्रस्ट में तो प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व मुख्य सचिव नृपेन्द्र मिश्रा, अमित शाह के गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सीबीएसई के अध्यक्ष प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के नौकरशाह भी शामिल हैं।

यानी यह साफ है कि मंदिर के संचालन में सरकारी नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में था। उसी नियंत्रण का फायदा उठाकर पिछले ढाई साल से यह बेरोकटोक लूट जारी है। अब जैसे ही यह घटना उजागर हो गयी, वैसी ही प्रधानमंत्री समेत भाजपा और आरएसएस के तमाम नेता इस घटना से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से राम मंदिर में हुई चोरी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बस 'राम-राम' कहकर पत्रकारों को टाल दिया। जबकि इन्हीं भागवत ने राम मंदिर के उद्घाटन के दिन कहा था कि मोदी जी को जो करना था, वह उन्होंने कर दिया, अब हमारी बारी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमें धर्म की स्थापना करनी है। भ्रष्टाचार के सवाल पर भागवत की चुप्पी कैसी धर्म की स्थापना के लिए है!

जिन प्रधानमंत्री ने आज इतनी बड़ी घटना में खुद को बचाने के लिए चुप्पी साधने वाला सबसे बेहतर तरीका चुना है, उन्होंने ही उस विशाल समारोह में सारे प्रचार का फोकस अपने पर केन्द्रित कर अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए कहा था कि राम मंदिर की स्थापना से एक नये युग की शुरुआत हुई है, राम राज्य की शुरुआत हुई है। क्या यही प्रधानमंत्री का राम राज्य है? क्या यही उनके 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' के वादे को पूरा करना है? क्या यही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है? वर्ना इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी वे चुप क्यों हैं? चोरी की घटना का विरोध करने में क्यों उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के दिन जैसी सक्रियता नहीं दिखाई? दरअसल, उस दिन उन्हें राम मंदिर को सामने रखकर हिन्दू वोटों को एकजुट करने की जरूरत थी। आज उन्हें मंदिर चढ़ावा के लुटेरों से दूरी बनाये रखने की जरूरत है।

लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार क्यों? क्या यह सिर्फ लोभ-लालच की वजह से है? आज लोगों को यह कड़वा सच समझना होगा कि जो लोग घोर प्रतिक्रियावादी, भ्रष्ट और सड़ी-गली इस मौजूदा पूंजीवादी राजसत्ता की सेवा करेंगे, उसे टिके रहने में मदद करेंगे, उनका भ्रष्ट होना तय है। धर्म जब तक समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक औजार था, तब तक उसने चरित्रों का निर्माण किया। लेकिन आज जब धर्म स्वार्थी और शोषक-शासक वर्ग का औजार बन गया है, तो धर्म का आडम्बर घोर प्रतिक्रियावादी और भ्रष्ट चरित्र ही पैदा करेगा। राम मंदिर घोटाले ने आज इस सच्चाई की एक बार फिर पुष्टि कर दी। □

मेरठ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी का विरोध, दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग

8 जुलाई 2026 को मेरठ कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ मेरठ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी का विरोध करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमिटी के सचिव कॉमरेड विजयपाल सिंह ने 11 जुलाई को जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि 15 मई 2026 को मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के गांव की छात्रा परीक्षा देने घर से गई थी। परीक्षा के उपरांत जब वह रात तक घर नहीं आई, तब उसके परिजनों ने 16 मई को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। इस घटना के संबंध में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर 8 जुलाई को मेरठ में कुछ संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की गई थी। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जब आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे, तो गेट बंद कर दिया गया।

ऐसी स्थिति में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। जिला प्रशासन

द्वारा सहानुभूतिपूर्वक बातचीत करके इस धरने को समाप्त कराया जा सकता था। लेकिन ऐसा करने की बजाय एसएसपी मेरठ द्वारा आंदोलनकारियों को स्वयं चांटे लगाये गए और अपशब्द बोले गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बैठे हुए एक प्रदर्शनकारी पर पुलिस वाहन में घुसकर एसएसपी ने थप्पड़ बरसाये। पुलिस की यह कार्रवाई जनतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन और कानून के शासन की अवधारणा के विरुद्ध है। जिले में कानून का शासन लागू करने की जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर वह खुद ही कानून का उल्लंघन कर लोगों के साथ ज्यादती करे, तब तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है।

ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि घटना की निष्पक्ष जांच करायी जाए और उक्त घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनसम्मत कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

नासिरनगर में तोड़फोड़ ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

यही नहीं, अलग-अलग सरकारी महकमों द्वारा बेटुके बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश ही यह साफ करती है कि यह सत्ता में बैठे लोगों की शह पर गुपचुप तरीके से की गई एक सोची-समझी कार्रवाई थी। सूरत के नासिरनगर इलाके के एक निवासी ने इस तोड़फोड़ के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। कतारगाम के विधायक विनु मोरडिया के मुताबिक, महानगर निगम के कमिश्नर और अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वे सिर्फ जमीन और सड़क नापने वहां गए थे और तोड़फोड़ में इस्तेमाल की गई मशीनें नगर निगम की नहीं थीं।

अगर नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, तो फिर किसके इशारे पर यह कदम उठाया गया? इस बीच, नगर निगम (एसएमसी) की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने सफाई दी कि निगम ने सिर्फ इलाके में जमीन की पैमाइश के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी थी और इस तोड़फोड़ में नगर निगम का कोई हाथ नहीं था। वहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन ने भी साफ किया कि एसएमसी की टीम सिर्फ नाप-जोख के काम से वहां गई थी। इस तरह की गोलमोल बातें प्रशासनिक मिलीभगत की तरफ साफ इशारा करती हैं। मीडिया के एक तबके ने इसे बिल्कुल ठीक कहा है कि यह एक "भूतिया तोड़फोड़" (अदृश्य ताकत द्वारा की गई कार्रवाई) थी।

यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि नासिरनगर कोई रातों-रात सरकारी जमीन पर कब्जा करके बसी हुई नई बस्ती नहीं है। यहां रहने वाले लोग पिछले कई दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं। उनके पास 1996 के समय की टैक्स की रसीदें, बिजली के बिल और दूसरे ऐसे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जो यह साबित करते हैं कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। यह बस्ती धीरे-धीरे एक स्थाई कामकाजी तबके के मोहल्ले में बदल चुकी थी, जहां के लोग मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे-मोटे कारोबारी के रूप में

शहर की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे थे।

वहां के बासिन्दों के मुताबिक, पिछले कई महीनों से उन पर यह जगह खाली करने का भारी दबाव बनाया जा रहा था। प्राइवेट बिल्डरों से जुड़े एजेंट बार-बार इस इलाके के चक्कर काट रहे थे और लोगों को जल्द से जल्द यहां से चले जाने की धमकियां दे रहे थे। लोगों को डराया जा रहा था कि अगर वे खुद से यह जगह खाली नहीं करेंगे, तो आखिरकार बुलडोजर चलाकर उनके घरों को ढहा दिया जाएगा।

इस बढ़ते खतरे को भांपते हुए, वहां के लोगों ने एकजुट होकर 15 अक्टूबर 2025 को म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कतारगाम के जोनल ऑफिसर और स्थानीय पुलिस स्टेशन को एक लिखित शिकायत सौंपी थी। उस शिकायत पत्र पर लगी सरकारी मोहरें यह साबित करती हैं कि सरकारी तंत्र को इस विवाद और निवासियों के डर की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई ठोस मदद या सुरक्षा नहीं दी गई।

नासिरनगर की यह घटना कोई इकलौती वारदात नहीं है, बल्कि यह गरीबों को उनके आशियाने और जमीनों से जबरन बेदखल करने के उसी पुराने ढर्रे को दिखाती है, जिसके तहत खाली करायी गई कीमती जमीन को बड़े कॉर्पोरेट घरानों के रियल एस्टेट सिंडिकेट (भू-माफियाओं) के हवाले कर दिया जाता है। सत्ता में बैठे लोग इसे 'व्यावसायिक विकास', शहर का 'सुन्दरीकरण' और 'आधुनिकीकरण' का नाम देते हैं। सत्ता पर काबिज कट्टर हिंदू सांप्रदायिक भाजपा सरकार के राज में अक्सर बेसहारा और गरीब अल्पसंख्यक समुदाय ही इस तरह की कार्रवाइयों का आसान निशाना बनता है।

नागरिकों के संगठन 'सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेकुलरिज्म' (सीपीडीआरएस) की गुजरात इकाई ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को एक याचिका भेजी है, जिसमें उनसे इस मामले में दखल देने और बेघर हुए लोगों को तुरंत दोबारा बसाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है। ●

आज देश आजाद हो चुका है—चाहे वह जिस भी रूप में क्यों न हो। आजादी 'कम्प्रोमाइज' (समझौते) से आयी और उसके दुष्परिणाम क्या हुए—मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। अलबत्ता, देश के बंटवारे से हुए गंभीर नुकसान के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसकी वजह से एक भौगोलिक सीमा के अंदर एकीकृत एक विशाल राष्ट्र, एकताबद्ध जनता, विशाल जनसमुद्र, लोगों के विशाल जनसमूह को जबरदस्ती दो भागों में बांट दिया गया, दो राष्ट्र, दो देश बना दिये गये। नतीजतन, राजनीतिक तौर पर दोनों मुल्कों के अंदर, दोनों देशों की जनता के बीच बैरभाव तथा अंधता, धर्मान्धता, धार्मिक कट्टरता व साम्प्रदायिक दंगों के जो बीज हमेशा के लिए साम्राज्यवादी बो गये थे, उन्हें पनपाया गया। लोगों के न चाहते हुए भी उनकी इच्छा के विरुद्ध, समझौते के जरिये आजादी हासिल करने से जो नुकसान हुआ, यह तो उसका एक पहलू है। इतने नुकसान उठाकर भी साम्राज्यवादियों से समझौते के जरिये जो आजादी मिली और उससे जो राजसत्ता व सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था देश में स्थापित हुई, वह लोगों के हितों को पूरी तरह से नकारते हुए मालिकों, पूंजीपतियों के हित में कायम हुई। इसलिए हमारे स्वाधीन व सार्वभौम राष्ट्र का असली 'डिक्टेटर' (एकछत्र सत्ताधीश) पूंजीपति वर्ग ही है। जबकि देश के आजादी आंदोलन में आम लोग ही लड़े-मरे।

एक राष्ट्र, एकताबद्ध लोगों को जबरन दो हिस्सों में बांट दिया गया

—शिवदास घोष

संसदीय चुनावों के जरिए सरकार बदलने के बारे में यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जब लोगों का किसी खास गवर्नमेंट से मोहभंग हो जाता है और वे आक्रोशित हो जाते हैं, तो चुनावों के जरिये एक दूसरी गवर्नमेंट कायम कर दी जाती है। आम लोग कुछ व्यक्तियों को बेईमान समझते हैं। वे सोचते हैं कि वैसे लोगों को हटाकर उनकी जगह

पर ईमानदार लोग आ जाने से ही उनका कल्याण हो जायेगा। बुर्जुआ पार्लियामेंटरी राजनेता किसी भी 'उसूल' या 'विचारधारा' की आड़ में लोगों को गुमराह करने की नीयत से इस किस्म के प्रचार का सहारा लिया करते हैं। इसलिए मैं मजदूरों, किसानों तथा आम लोगों से कहता हूं कि आप इस किस्म के भ्रम-जाल में न पड़ें। क्योंकि महज गवर्नमेंट के बदलने से आम लोगों की बुनियादी समस्याएं हल नहीं हो सकतीं, हल



नहीं की जा सकतीं। पार्लियामेंटरी व्यवस्था के अन्तर्गत चाहे जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार क्यों न दिये जायें, चाहे जो भी कानून क्यों न पास कर दिये जायें, लोगों को रिलीफ देने के लिए चाहे जितनी भी योजनाएं क्यों न अपनायी जायें, जनता को मुक्ति नहीं मिलेगी। बल्कि इसके विपरीत लोगों की हालत दिन-प्रति-दिन बद से बदतर होती जायेगी।

राजसत्ता में मौलिक परिवर्तन किये बिना इस तरह से सरकारों की अदला-बदली होने से क्या होता है? ऐसे में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति भी सरकार में आता है, तो उससे और भी ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि आम लोगों का उन पर विश्वास होता है। ईमानदार होते हुए भी अगर वह गुमराह हो गया और अगर वह क्रांति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सका, तो उसके पास पूंजीपतियों का दलाल बनने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। उसे पूंजीवादी

व्यवस्था में ही सुधार लाकर उसे सुदृढ़ करना होता है। जबकि उसके प्रति लोगों के विश्वास के चलते कुछ दिनों के लिए ही सही, जनता का विश्कोभ व असंतोष शांत हो जाता है। इसलिए ऐसे तथाकथित ईमानदार 'एडमिनिस्ट्रेटर' (प्रशासक) के कार्यकाल में बुर्जुआ शासन को, पूंजीवादी शासन को और ज्यादा सुदृढ़ व ठोस बुनियाद पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त होता है। जवाहर लाल के नेतृत्व में भारतीय पूंजीवाद की जड़ें और ज्यादा गहरी व मजबूत हुईं तथा वह और सुदृढ़ हुआ। इसलिए लेनिन ने कहा था कि ईमानदार और बेईमान पादरी में बेईमान पादरी एक मायने में बेहतर होता है। बेईमान होने के चलते वह बेहतर नहीं होता, बल्कि वह बेहतर इसलिए होता है कि लोग उसे आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ईमानदार व भ्रमित पादरी लोगों को यह बताता फिरे कि वे दुखी एवं मुसीबत-जदा इसलिए हैं, क्योंकि उनकी किस्मत ही ऐसी है, तो ऐसा करते हुए लोगों को क्रांति से दूर रखने का उसका यह कृत्य लोगों का ज्यादा नुकसान करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं और वह हर तरह के शोषण के खिलाफ संघर्ष से, जिस संघर्ष में उनकी मुक्ति निहित है, कन्नी काटने और दूर रहने की उन्हें सीख देता रहता है।

(15 अगस्त की आजादी और जन मुक्ति की समस्या)

फीफा (FIFA) वर्ल्ड कप — खेलों का राजनीतिकरण और व्यापारीकरण

जैसा कि हम सभी जानते हैं, खेल चरित्र निर्माण का एक बेहतरीन जरिया है। यह शारीरिक और मानसिक पोषण बनाये रखने का एक साधन है—स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बनाने और आपसी सौहार्द व दोस्ती की भावना को पैदा करने का एक तरीका है। खेल भावना एक ऐसी मनोवृत्ति है, जो निष्पक्ष खेल, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार, नैतिक व्यवहार व ईमानदारी और जीत या हार में शालीनता बनाये रखने की कोशिश करता है। निष्पक्ष खेल का मतलब है कि सभी प्रतिभागियों को जीत हासिल करने का समान मौका मिले और वे दूसरों के साथ ईमानदारी, स्पष्टता और मजबूती व सम्मानजनक तरीके से पेश आयें, तब भी जब कि दूसरे निष्पक्ष रूप से न खेलें। इसमें टीम के सदस्यों, विरोधियों और अधिकारियों सहित दूसरों का सम्मान करना शामिल है। चरित्र का मतलब है वे स्वभाव, मूल्य और आदतें, जो यह तय करती हैं कि कोई व्यक्ति आम तौर पर इच्छाओं, डर, चुनौतियों, अवसरों, असफलताओं और सफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और यह विशेष तौर पर दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार में दिखता है, जैसे किसी विरोधी को उठने में मदद करना या मैच के बाद हाथ मिलाना।

इस प्रकार, खेल सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना लाने का जमाने से एक आजमाया हुआ जरिया है। इसीलिए खेल को हमेशा शिक्षा का पूरक माना गया है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की शुरुआत

1896 में फ्रांसीसी शिक्षक बैरन पियरे डी कूबर्टिन ने ओलंपिक खेलों को, जो प्राचीन ग्रीस में ईस्वी पूर्व 776 में ज्यूस के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव के रूप में शुरू हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना करते हुए फिर से शुरू किया। फुटबॉल, कुलीन खेलों के विपरीत, औद्योगिक कस्बों और मजदूर

वर्ग के समुदायों में पैदा हुआ था। यह खेल 19वीं सदी के ब्रिटिश पब्लिक बोर्डिंग स्कूलों में अव्यवस्थित ग्रामीण मनोरंजन से एक संगठित खेल में बदल गया और जल्द ही प्रवासियों के माध्यम से महाद्वीपों में फैल गया।

इसी तरह, फीफा वर्ल्ड कप की कल्पना उस आदर्श के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में की गई थी और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों की टीमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से खेलों के स्तर को ऊपर उठाने का एक मौका था। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1928 में आयोजित किया गया था। यह देखा जा सकता है कि फुटबॉल और ओलंपिक दोनों में ही, तत्कालीन समाजवादी देशों, सोवियत संघ से लेकर पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और अन्यो का प्रदर्शन बहुत उल्लेखनीय था। पूंजीवादी वैश्वीकरण और समाजवादी गुट के दुखद विघटन से पहले फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन मुख्य रूप से खेल में उत्कृष्टता और प्रतिस्पर्द्धा की भावना पर केंद्रित थे। खेलों की बागडोर मोटे तौर पर खेल-प्रेमी लोगों के हाथों में थी।

खेलों का बिकाऊ माल बनना

लेकिन जब एक-ध्रुवीय दुनिया में पूंजीवादी वैश्वीकरण आया, तो खेलों को व्यापारीकरण और व्यावसायीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया धनाढ्य केरी पैकर ने 50-ओवर वाले 'पायजामा क्रिकेट' की शुरुआत की और टेस्ट व वनडे क्रिकेट से मिलने वाली कमाई के 5 से 10 गुना अधिक पैसा देने का लालच देकर उस समय के ज्यादातर मशहूर क्रिकेटर्स को इसमें शामिल कर लिया। तब से खेल एक आनंदोत्सव जैसा बनना शुरू हो गया। पश्चिमी देशों और हमारे देश में भी बड़े व्यापारिक घरानों ने मशहूर फुटबॉल क्लबों को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वे उपभोक्ता दर्शकों को खेल बेचकर मुनाफा कमा सकें। हर भावनात्मक अनुभव एक बिकाऊ माल बन जाता है।

साम्राज्यवादी-पूंजीवादी दुनिया, या यूं कहें कि व्यापारिक घरानों और अमीर लोगों की एक अपवित्र सांठगांठ ने अपने नए तरह के संचार माध्यमों—इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर टीवी—के जरिये एक सुनियोजित और चालाकी भरा प्रचार शुरू किया। नए शब्द चलन में आए; जैसे पेशेवरपन, प्रायोजकता, सूचनोरंजन यानी सूचना और मनोरंजन का मिश्रण वगैरह। एक तरफ, खेल की दुनिया में पैसे की भारी आवक हुई और साथ ही यह प्रचार भी किया गया कि शौकिया खेलों का जमाना अब बीत चुका है। खेल और व्यवसाय को बहुत गहराई से आपस में जोड़ दिया गया।

जैसा कि अंदेशा था, इस सांठगांठ और व्यापारिकता-व्यावसायिकता की विचारधारा ने भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया। सट्टेबाजी, परिणामों के पूर्व निर्धारण, रिश्वतखोरी, मादक द्रव्यों के सेवन के जरिये गैर-कानूनी और कृत्रिम रूप से प्रदर्शन बेहतर बनाना आदि, हर खेल में, चाहे वह कोई भी देश हो, आम बात हो गई। जल्द ही हालात इतने बिगड़ गए और लोगों के सामने इनकी सच्चाई आने से उनके मन में इतनी बुरी राय बनी कि अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में, आयोजकों को कम से कम दिखावे के लिए ही सही, सट्टेबाजी और फिक्सिंग जैसी कोशिशों के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह समस्या खासकर फुटबॉल में साफ तौर पर देखी गई। यहां तक कि सबसे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, नतीजों को प्रभावित करने के लिए मैच फिक्स करने या खिलाड़ियों के प्रदर्शन में हेरफेर करने की खबरें सामने आईं।

फीफा वर्ल्ड कप: पैसे की भारी बर्बादी वाला इवेंट

इसी क्रम में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2026 फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा भव्य आयोजन बन गया है, जिसमें बहुत ज्यादा महंगी टिकटें, रहने-सहने के महंगे इंतजाम, बढ़ते यातायात

खर्च और कुछ वैश्विक मीडिया दिग्गजों को बहुत ज्यादा कीमत पर मीडिया अधिकार बेचना शामिल है। इस आयोजन के हर पहलू पर प्रायोजकों का दबदबा कायम रहता है। आवभगत पैकेज अमीर ग्राहकों के लिए होते हैं। मेजबान शहर जनता का पैसा खर्च करते हैं, जबकि निजी कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। व्यावसायिक प्रायोजक और खास मेहमानों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जबकि लाखों आम समर्थक और फुटबॉल के असली चाहने वाले इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस तरह, बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफा कमाने की होड़ में 'लोगों के खेल' की भावना का गला घोट दिया जाता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। 48 टीमों वाले फीफा 2026 वर्ल्ड कप पर संकीर्ण भू-राजनीतिक गुटबाजी, नस्लवाद और ऐसी ही अन्य बातों का दाग लगा है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा खेलों के मकसद, सार्वभौमिक भावना, बहुसंस्कृतिवाद और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के खिलाफ हैं।

भेदभावपूर्ण व्यवहार की भरमार

फीफा के अमीर अधिकारियों ने आयोजन के लिए अमेरिका आने वाले खिलाड़ियों, कर्मचारियों या समर्थकों की सुरक्षा हेतु कुछ नहीं किया है। अमेरिकी सरकार की नस्लवादी आब्रजन और प्रवेश नीतियों (जो यह तय करती हैं कि कौन भाग ले सकता है) पर उनकी मौन-सम्मति इन नीतियों को और मजबूत करती है। फीफा ने सब कुछ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के हाथों में छोड़ दिया है। चार देशों—हैती, ईरान, आइवरी कोस्ट और सेनेगल—को किसी भी तरह के वीजा पर सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप में शामिल अल्जीरिया और केप वर्डे जैसी टीमों वाले देशों सहित 52 अफ्रीकी, कैरेबियाई और दक्षिण एशियाई देशों के प्रशंसकों को पर्यटन वीजा

(शेष पृष्ठ 7 पर)

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपरलीक, स्मार्टमीटर, बिजली के निजीकरण, स्कूल बंद करने आदि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रेष प्रदर्शन



ग्वालियर

महंगाई, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली, बिजली के बढ़ते दामों व स्मार्ट मीटर, प्रदेश के 94000 सरकारी स्कूलों को बंद किये जाने, सरकारी अस्पतालों के निजीकरण, अश्लीलता, नशाखोरी व महिलाओं पर बढ़ते अपराधों व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एवं स्थानीय मुद्दों को लेकर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने 14 जुलाई को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन दिवस के तहत जिलों में प्रदर्शन किये।

गुना : एसयूसीआई (सी), गुना इकाई की ओर से स्थानीय नगरपालिका के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को जिला सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव, जिला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड लोकेश शर्मा, ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड नरेंद्र सिंह भदौरिया, कॉमरेड श्रीराम सेन, कॉमरेड शोभना श्रीवास्तव, कॉमरेड शानू भिलाला और कॉमरेड सीमा राय ने भी सम्बोधित किया। संचालन कॉमरेड विकास बंसल ने किया।



जबलपुर

ग्वालियर : राज्यव्यापी विरोध दिवस पर ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। **भोपाल** : एसयूसीआई (सी) की भोपाल जिला कमेटी की ओर से जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में आयोजित विरोध प्रदर्शन को पार्टी के जिला कार्यालय सचिव कॉमरेड विनोद लोगारिया व जिला सचिव कॉमरेड मुदित भटनागर ने संबोधित किया। मंच संचालन जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड सतीश ओझा ने किया। **इंदौर** : एसयूसीआई (सी) की इंदौर इकाई द्वारा विभिन्न बस्तियों में विरोध प्रदर्शन किया गया। **देवास** : देवास में पार्टी की जिला सांगठनिक कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। **सागर** : राज्यव्यापी विरोध दिवस पर स्थानीय बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य वक्ता जिला सचिव कॉमरेड रामावतार शर्मा रहे। **जबलपुर** : जबलपुर में मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र-नौजवान, मजदूर-किसान, सभी परेशान हैं। सरकार संवेदनहीनता दिखाते हुए महंगाई को काबू करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा तानाशाही तरीके से आम लोगों पर जनविरोधी काले कानून थोपे जा रहे हैं। आम लोगों की इच्छा के विपरीत स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली को लगातार महंगा किया जा

रहा है और मध्य प्रदेश की बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथों सौंपी जा रही है। स्मार्ट सिटी आदि के नाम

पर बस्तियां-दुकानें आदि तोड़ी जा रही हैं। न तो मुआवजा दिया जा रहा है और न ही उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। युद्ध की आड़ में बढ़ाये गए पेट्रो-पदार्थों के दाम कम नहीं किये जा रहे हैं, जबकि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम लगातार गिर रहे हैं। देश में सरकारी स्कूल लगातार बन्द हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश के बंद हुए हैं। महिलाओं व बच्चियों की अस्मिता खतरे में है। कर्मचारियों से पेंशन का अधिकार तक छीन लिया जा रहा है। स्थाई भर्तियों पर अघोषित रोक लगा दी गई है। लगातार पेपर लीक और भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद सरकार बेशर्मी

से इसी तंत्र की सुरक्षा में लगी हुई है। इन सभी विषम हालातों से निपटने के लिए आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है।

देवास



बाल विकास गतिविधियों का शानदार आयोजन

दिल्ली।

दिल्ली के कौडली क्षेत्र में बाल विकास गतिविधियों के लिए 27 व 28 जून को दो दिवसीय कैम्प आयोजित किया गया।

पहले दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए उनके चित्र पर शहीद व मनीषी यादगार मंच के संयोजक डॉक्टर जय सिंह, नवीन राम तथा छात्र संगठन ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन

(एआईडीएसओ) की तरफ से कॉमरेड श्रेया सिंह ने फूल अर्पित किये।

दो दिन तक एआईडीएसओ ने मैजिक व साइंस शो, गाना सीखने आदि की विभिन्न गतिविधियां करवायीं। इनमें बच्चों ने काफी उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय व राजेश सहित अनेक स्थानीय युवाओं ने बहुत मदद की।



फॉक्सवैगन के वर्कर्स सहित आम वर्कर्स के साथ एकजुटता का पैगाम

दुनियाभर में एक लाख नौकरियों में कटौती, प्लांटबंदी-कारखानाबंदी और इस प्लांट को छोड़कर नौकरी के लिए हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री में चले जाने की वर्कर्स को सलाह दिये जाने के खिलाफ वीडब्ल्यू ग्रुप कंपनियों के संघर्षरत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्कर्स के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हुए ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 7 जुलाई को जारी प्रेस बयान में कहा :

“हम, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी), जो भारत में एक केन्द्रीय ट्रेड यूनियन है और भारतीय मजदूरों की तरफ से महाराष्ट्र के पुणे और औरंगाबाद जिलों में भारत समेत पूरी दुनिया में जर्मनी आधारित ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फॉक्सवैगन ग्रुप के संघर्षरत वर्कर्स के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हैं। ये वर्कर दुनियाभर में एक लाख नौकरियों में कटौती और कई प्रोडक्शन प्लांटों को बंद करने के

प्रस्ताव के खिलाफ हैं, जिसकी घोषणा इसके इग्जेक्यूटिव बोर्ड के सीईओ मिस्टर ओलिवर ब्लूम ने की है। हम वीडब्ल्यू ग्रुप के इग्जेक्यूटिव बोर्ड के उस साम्राज्यवादी विचार की निंदा करते हैं, जिसमें वर्कर्स को हथियार इंडस्ट्री में जाने की सलाह दी गई है। हम अखबारों के कई वितरकों और वर्कर्स पार्टी एमएलपीडी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की भी निंदा करते हैं, जो प्रस्तावित नौकरी में कटौती और 4 प्रोडक्शन प्लांटों को बंद करने के खिलाफ वर्कर्स के संघर्ष का समर्थन कर रहे थे।

हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स के ग्लोबल संगठन आईसीओआर की कोशिशों का समर्थन करते हैं ताकि उन्हें नौकरी में कटौती, प्लांटों को बंद करने और दूसरे दमनकारी तरीकों के खिलाफ एकजुट किया जा सके।

दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ!
क्रांतिकारी अभिवादन के साथ!

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ एसयूसीआई (सी) का संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन



संग्रामपुर, बिहार।

विभिन्न जन समस्याओं के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की संग्रामपुर लोकल कमेटी के बैनर तले 17 जुलाई को थाना चौक मोड़ से सैकड़ों किसानों, मजदूरों, नौजवानों और महिलाओं ने जुलूस निकाला। जुलूस बाजार के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए प्रखंड मुख्यालय के समक्ष पहुंचा। जुलूस में कार्यकर्ता हाथों में लाल झंडा और जन मुद्दों से संबंधित नारे लिखी हुई पट्टिकाएं लिये हुए थे। जुलूस का नेतृत्व लोकल कमेटी सचिव कॉमरेड रणजीत राम व सुधीर यादव संयुक्त रूप से कर रहे थे।

पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने मांगों से संबंधित स्मार-पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को सौंपा। स्टेट बैंक के नजदीक जमा पानी की निकासी, बस स्टैंड में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, खाद-बीज की कालाबाजारी पर रोक, सभी गांवों के टोले-मोहल्ले में पानी निकासी, सभी महादलित परिवारों को बसने योग्य 5 डिसमिल जमीन, स्वास्थ्य केन्द्र संग्रामपुर में महिला चिकित्सक की पद स्थापना, नगर पंचायत में बाधित प्रधानमंत्री आवास कार्य को अविलंब शुरू करने, रायकड़ टाड़ी की नदी में रुके पूल का निर्माण कार्य आरंभ करने, रतनपुरा गांव में बनी पानी की दो टंकियों को दबंगों के कब्जे से छुड़ाकर पेयजल की शीघ्र आपूर्ति करने, शराबबंदी के बावजूद रतनपुरा व सुखदेव नगर में धड़ल्ले से बिक रही शराब पर पूर्ण रोक लगाने, प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों

में जरूरतमंद महादलित परिवार के लिए 5 डिसमिल भूमि का बंदोबस्त करने की मांग की गई।

जुलूस वहीं सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड उत्तम दास कर रहे थे। मौके पर मौजूद पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड कृष्णदेव साह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र, किसान, मजदूर-सभी परेशान हैं। सरकार संवेदनहीनता दिखाते हुए महंगाई को काबू करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथों सौंपी जा रही है। स्मार्ट सिटी आदि के नाम पर बस्तियां और गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। युद्ध की आड़ में बढ़ाये गए डीजल व पेट्रोल के दाम कम नहीं किये जा रहे हैं। स्थाई भर्तियों पर अघोषित रोक लगा दी गई है। लगातार पेपर लीक और भ्रष्टाचार होने के बावजूद सरकार बेशर्मी से इसी तंत्र की सुरक्षा में लगी हुई है। उन्होंने कहा इन सभी विषम हालातों से लड़ने के लिए आंदोलन ही समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता है।

सभा में नारायण यादव, मंटू यादव, सधीर मंडल, गंगा मंडल, भारत मंडल, सुशीला देवी, जितेंद्र मांझी, चरित्र मांझी, महिला नेत्री गीता कुमारी, वकील यादव, संतोष दास, पिटू राम, देवानंद यादव आदि उपस्थित थे।

नागरिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जनसभा



दिल्ली: जनसभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड रमेश पराशर

दिल्ली : लोगों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन खड़ा करने के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की पश्चिमी जिला कमेटी द्वारा 12 जुलाई को गुजराती समाज भवन में एक जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

जनसभा के अतिथि वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर अपूर्वानंद और मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) के दिल्ली राज्य

कमेटी सदस्य कॉमरेड रमेश पराशर ने सभा को संबोधित किया। इनके अलावा विभिन्न इलाकों से आये प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी।

दिल्ली में बस्तियां न उजाड़ने, अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने, क्षेत्र में फैली गंदगी दूर करने, पीने का साफ पानी मुहैया कराने, सड़कों, नालों व पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने और सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की गई। मर्जर के नाम पर

सरकारी स्कूल बंद करने व प्रवेश परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराधों, नशाखोरी व प्रचार माध्यमों से परोसी जा रही अश्लीलता और लगातार बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ पेश किया गया प्रस्ताव सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अंत में वक्ताओं ने तमाम जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन को और भी व्यापक स्तर पर ले जाने और लोगों को संगठित होकर आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

आजीवन क्रांतिकारी ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

विभिन्न राज्यों में जिम्मेदारियां निभा रहे थे।

1994 में कॉमरेड रबिन समाजपति एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य चुने गये। लेकिन बाद में बिहार पार्टी संगठन में आयी कुछ समस्याओं की वजह से पार्टी के निर्देश पर वे बिहार चले गये। वहां उनकी भूमिका ने बहुत जल्द ही उन्हें कॉमरेडों का प्रिय नेता बना दिया। उसके बाद प्रशासनिक तौर पर बिहार राज्य के दो हिस्सों में बंट जाने के बाद पार्टी ने उन्हें झारखंड भेज दिया। बीमारी की हालत में भी उन्होंने उस जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक अपनी मृत्यु के पहले तक पालन किया। 2012 में वे पार्टी के झारखंड राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव मनोनीत किये गये। 2018 में वे पार्टी के स्टाफ सदस्य बने और इसी साल पार्टी की तीसरी कांग्रेस में वे केन्द्रीय कमेटी के सदस्य चुने गये। आगे चलकर 2021 में वे पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य चुने गये। उन्होंने पार्टी संगठन की जरूरत से राजस्थान का भी दौरा किया।

वे विभिन्न शारीरिक समस्याओं की वजह से अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे। लेकिन इससे पार्टी की कोई भी जिम्मेदारी निभाने में कोई अड़चन नहीं आयी। इतिहास और ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रति उनमें गहरा लगाव था।

कॉमरेड रबिन समाजपति अपनी कमी-खामियों के बारे में कहा करते थे कि अगर कोई मेरी कमी-खामी जानने के बाद भी मुझसे स्नेह-प्यार करता है, तो वह असली और ठोस स्नेह-प्यार है और अगर कोई इसे जाने बिना स्नेह-प्यार करता है, तो उसमें खोखलापन रहना लाजिमी है। उनकी कमी-खामियों को लेकर जूनियर कॉमरेड भी बेहिचक आलोचना कर सकते थे। अगर उन्हें किसी कॉमरेड की बातचीत में वर्ग दृष्टिकोण की कमी दिखती या फिर नेतृत्व के प्रति समर्पण की कमी झलकती, तो वे उस कॉमरेड को समझाने की कोशिश करते। वे आत्म प्रचार पसंद नहीं करते थे। वे जूनियर कॉमरेडों को विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां देकर उन्हें आगे लाने की कोशिश करते थे।

मृत्यु से कई साल पहले विभिन्न जटिल बीमारियों की वजह

से उनकी सेहत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी आदि कई तरह के कष्ट उन्हें बर्दाश्त करने पड़े थे। उच्च रक्तचाप की समस्या तो थी ही, जिसकी वजह से इस बार मस्तिष्क रक्तस्राव इतना ज्यादा हो गया था कि डाक्टरों को कहना पड़ा कि ऑपरेशन करना संभव नहीं है। इसके दो दिन बाद ही उनका निधन हो गया।

एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के तौर पर कॉमरेड रबिन समाजपति ने जब जिस बात को सही समझा, जिस काम को करना उचित समझा, उसे पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटे। केन्द्रीय कमेटी तहेदिल से यह उम्मीद करती है कि उनके निधन से भारत के जन आन्दोलन और क्रांतिकारी आन्दोलन की जो क्षति हुई है, उसे पूरा करने के लिए कॉमरेड आगे आयेंगे।

कॉमरेड रबिन समाजपति लाल सलाम।



सरकार के गैर-लोकतांत्रिक कदम की एआईडीवाईओ ने की निंदा

नई दिल्ली : एआईडीवाईओ के अध्यक्ष कॉमरेड निरंजन नस्कर और महासचिव कॉमरेड अमरजीत कुमार ने 18 जुलाई को जारी बयान में कहा : “पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और शिक्षाविद सोनम वांगचुक, जो पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें आज पुलिस ने जबरन हटाकर

अस्पताल में भर्ती कराया। जंतर-मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

एक लोकतांत्रिक देश में यह अपेक्षित है कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों से सार्थक व शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करे और बातचीत के जरिये मसले का हल ढूँढ़े। लेकिन विरोध प्रदर्शन स्थल से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाना सरकार के तानाशाही चरित्र को दिखाता है।

सरकार की इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई की एआईडीवाईओ कड़ी निंदा करता है और देशभर के युवाओं से इस घटना का विरोध करने की अपील करता है।

मांगें: 1. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 2. एनटीए भंग की जाये। 3. प्रश्नपत्र लीक पर रोक लगे और जवाबदेही सुनिश्चित हो। 4. शांतिपूर्ण जनवादी आंदोलनों पर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई बंद हो।”

निर्माण मजदूरों की लंबित मांगें पूरी करने की आवाज बुलंद की

पंचकुला, हरियाणा।

गत 14 जुलाई को हरियाणा के निर्माण श्रमिकों की सभी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल की भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन रोहताश सिंह जांगड़ा व संयुक्त सचिव अजमेर सिंह देशवाल के साथ बैठक हुई।

इसमें एआईयूटीयूसी से संबद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा (रजि. नं. 1845) की ओर से कॉमरेड मेहर सिंह बांगड़ व कॉमरेड सुधीर शामिल हुए और निर्माण मजदूरों की विभिन्न

समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने निर्माण मजदूरों के पंजीकरण, नवीनीकरण, लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की मांग की और अन्य व्यावहारिक समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि निर्माण मजदूरों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) का अधिकार ट्रेड यूनियनों को दिया जाए ताकि वास्तविक निर्माण मजदूरों का समय पर पंजीकरण हो सके।



बिजली-पानी आदि मांगों पर एआईकेकेएमएस ने सौंपा ज्ञापन



तक पानी नहीं आता है। बिजली कटौती की भयंकर समस्या है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि 24 घंटे बिजली और स्वच्छ पेयजल का पूरा प्रबंध

बवानी खेड़ा, हरियाणा।

सुन्दर ब्रांच नहर में महीने में 15 दिन पानी छोड़ने की मांग को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस), जो कि संयुक्त किसान मोर्चे का एक महत्वपूर्ण घटक है, की बवानी खेड़ा ब्लॉक कमेटी ने 6 जुलाई को तहसील कार्यालय, बवानी खेड़ा में तहसीलदार, बवानी खेड़ा के माध्यम से सिंचाई मंत्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन कानूनगो शैलेश को दिया।

इस मौके पर एआईकेकेएमएस के जिला प्रधान कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि आज बिजली और पानी मूलभूत जरूरतें हैं, जो उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार जनता को बिजली, पेयजल और सिंचाई के लिए नहरी पानी भी पूरा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सरकार ‘हर घर नल’ की बात करती है, लेकिन नलों में कई-कई दिनों

करे, सुन्दर ब्रांच में पर्याप्त मात्रा में पानी महीने में 15 दिन दिया जाए और रजबाहों में पूरा एक हफ्ता पानी दिया जाए ताकि पानी की किल्लत न हो। आज पीने के पानी और सिंचाई के लिए नहरी पानी की विकट समस्या है, जबकि पहले इसी नहर से गन्ने की फसल भी उपजायी जाती थी। यह सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम है कि कभी बाढ़ और बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से फसल तबाह हो जाती है और कभी नहरों में पानी की कमी से फसल नहीं हो पाती है।

प्रदर्शन में संगठन के संगठन के जिला सचिव मास्टर बस्तीराम, बवानी खेड़ा ब्लॉक प्रधान कॉमरेड सतबीर सिंह बोहल, कॉमरेड फूल चन्द, महेंद्र सिंह, ब्लॉक कमेटी सदस्य मास्टर हनुमान रोहिला, रामकुमार, भागीरथ, गुलाब, ओमप्रकाश मदेरना, सन्दीप पपोसा, हरफूल, रामधारी यादव आदि ने भी शामिल थे।

राजनैतिक शिक्षण शिविरों का आयोजन



भोपाल, मध्य प्रदेश।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), राज्य कमेटी द्वारा कम्युनिस्ट आचरण विधि को लेकर 5-6 जुलाई को यहां दो दिवसीय राज्य स्तरीय एक्टिविस्ट राजनैतिक शिक्षण शिविर लगाया

रायपुर, छत्तीसगढ़।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) छत्तीसगढ़ राज्य सांगठनिक कमेटी की ओर से 12 जुलाई को एक राजनैतिक शिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें महान नेता कॉमरेड

गया। इस शिविर का संचालन पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सोमेन बसु, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सत्यवान और पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य और राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने किया।

शिवदास घोष की पुस्तक ‘क्रांतिकारी जीवन सबसे अधिक सम्माननीय’ पुस्तक पर आये सवालों पर चर्चा हुई। शिक्षण शिविर का संचालन पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य ने किया।

जनसमस्याओं को लेकर जनसभा



रेवाड़ी, हरियाणा।
ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के तत्वावधान में 12 जुलाई को रेवाड़ी जिले के गांव खटावली में एक जनसभा आयोजित की गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं समेत किसान, मजदूर और भूमिहीन परिवारों से लोग शामिल हुए। इसमें पड़ोसी गांवों से भी किसान आन्दोलन के हिमायती मित्रों ने भागीदारी की और अपने-अपने गांवों में जनसभाएं करवाने का संकल्प लिया।
जनसभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने मेहनतकशों के जीवन में चुभती हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब समस्याओं की जड़ मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था है। सरकारों की अदला-बदली होती रहती है, लेकिन नीतियां नहीं बदलती हैं। आन्दोलन के सिवा मेहनतकशों के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। प्रदेश के मेहनतकशों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए जोरदार आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत है। उन्होंने 25 अक्टूबर को महापंचायत में रोहतक चलने का न्योता दिया। इस मौके पर कॉमरेड शेर सिंह भी मौजूद थे।

बच्चियों व महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ रोष प्रदर्शन



मध्य प्रदेश।
प्रदेश व देशभर में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ और महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध के मूल कारण शराब, तमाम तरह के नशे, इंटरनेट मोबाइल के जरिये सोशल मीडिया द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता व अपसंस्कृति पर रोक लगाने और बारूडपुर (पश्चिम बंगाल) तथा श्री गंगानगर (राजस्थान) में बच्चियों से वीभत्स बलात्कार करने वाले अपराधियों को कठोर दंड देने की मांग को लेकर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहरों ग्वालियर, गुना, इंदौर आदि में प्रदर्शन किये।



श्रीगंगानगर की 13 वर्षीय बालिका को न्याय दो

अलवर, राजस्थान।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 जून से 22 जून तक विभिन्न होटलों में 13 वर्षीय लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और बाद में इलाज के दौरान हुई मौत की जघन्य घटना के खिलाफ नागरिकों के संगठन 'सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेकुलरिज्म' (सीपीडीआरएस) की अलवर जिला इकाई की ओर से 8 जुलाई को नंगली सर्किल पर रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मृतका के परिवार को त्वरित न्याय दिये जाने और इस जघन्य घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों को शीघ्र उदाहरणमूलक सजा देने और



एसयूसीआई (सी) पोलित ब्यूरो सदस्य व झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति की श्रद्धांजलि सभा आयोजित

पटना, बिहार।
एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी के तत्वावधान में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य व झारखंड राज्य सचिव तथा संयुक्त बिहार में 1995 से 2000 तक राज्य कमिटी के सदस्य रहे कॉमरेड रबिन समाजपति की श्रद्धांजलि सभा 10 जुलाई को गांधी संग्रहालय में आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने की वजह से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष आयोजित की गयी।
सभा की शुरुआत कॉमरेड रबिन समाजपति की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। कॉमरेड रबिन समाजपति की तस्वीर पर एसयूसीआई (सी) केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह बिहार राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह, राज्य कमिटी सदस्य कॉमरेड मणिकांत पाठक, कॉमरेड साधना मिश्रा, कॉमरेड अर्जुन कुमार, कॉमरेड सूर्यकर जितेन्द्र सहित राज्य कमिटी के अन्य तमाम सदस्यों और पार्टी के विभिन्न जन संगठनों के नेताओं ने माल्यार्पण किया।
उसके बाद सर्वहारा वर्ग के महान नेता तथा इस युग के प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक व चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत प्रस्तुत किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह बिहार राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह द्वारा पार्टी के दिवंगत पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रबिन समाजपति के प्रति श्रद्धांजलि संदेश पढ़कर सुनाने के बाद कॉमरेड रबिन समाजपति की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया।
श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांधी संग्रहालय में कॉमरेड रबिन समाजपति की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति ली गयी थी, लेकिन सभा की शुरुआत के ऐन मौके पर अनुमति वापस ले ली गयी और तानाशाही तरीके से सभा आयोजित करने पर रोक लगा दी गयी। भाजपा नेतृत्ववाली राज्य सरकार के इस कदम को फासीवादी कदम बताते हुए कॉमरेड सिंह ने कहा यह सरकार और प्रशासन का यह कदम लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर जबरदस्त हमला है। आदर्श चुनाव संहिता के नाम पर हॉल में भी सभा करने, यहां तक कि श्रद्धांजलि सभा भी करने की अनुमति न देना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का सरेआम हनन है। कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने कॉमरेड रबिन समाजपति के बारे में अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा कि कॉमरेड रबिन समाजपति आत्म प्रचार विमुख थे। वे हमेशा जूनियर कॉमरेडों को विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां देकर उन्हें आगे लाने की कोशिश करते थे। उनका पूरा जीवन छात्र आन्दोलन व जन आन्दोलन के निर्माण तथा पार्टी संगठन के सुदृढ़ीकरण व विस्तार में बीता। एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के तौर पर कॉमरेड रबिन समाजपति ने जब जिस बात को सही समझा, जिस काम को करना उचित समझा, उसे पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। कॉमरेड सिंह ने आशा व्यक्त की कि उनके निधन से भारत के जन आन्दोलन, क्रांतिकारी आन्दोलन और पार्टी की जो क्षति हुई है, उसे पूरा करने के लिए पार्टी कॉमरेड आगे आयेगे।
श्रद्धांजलि सभा को भाकपा माले के नेता कमलेश शर्मा ने भी संबोधित किया। अंत में अंतर्राष्ट्रीय गान से सभा का समापन हुआ।



एचपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई की एआईयूटीयूसी ने की निंदा

हिसार, हरियाणा।
केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन (एचपीएससी) की चयन प्रक्रिया में लगायी गई कथित नाजायज शर्तों के विरोध में पंचकूला सेक्टर-5 में धरना दे रहे और आमरण अनशन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की। संगठन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा अभ्यर्थियों की मांगों को मानने की सरकार से मांग की। एआईयूटीयूसी के प्रदेश सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश और प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड मेहर सिंह बांगड़ ने 30 जून को जारी बयान में कहा कि आयोग ने परीक्षा के बाद नई शर्तें थोपकर अनेक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में रिक्त पदों के बावजूद योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जा रहा है, जबकि इनमें पीएचडी और नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी भर्ती करने के बजाय अस्थायी नियुक्तियों को बढ़ावा दे रही है। संगठन का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे अभ्यर्थियों को रात में गिरफ्तार कर लिया गया और धरना स्थल से उनका टेंट भी हटा दिया गया। यह कार्रवाई घोर निन्दनीय है।
एआईयूटीयूसी ने सरकार से मांग की है कि एचपीएससी की विवादित शर्तों को वापस लेकर सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाये।

फीफा वर्ल्ड कप ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

पाने के लिए बॉन्ड पेमेंट के तौर पर अनिवार्य रूप से 5,000 डॉलर से 15,000 डॉलर तक जमा करने पड़े। अफ्रीकी देशों और हैती के लोगों को यात्रा के अधिकार से जानबूझकर वंचित रखने के कारण प्रशासकों, स्वास्थ्य-कर्मियों, अनुवादकों और अन्य कर्मचारियों को वीजा मिलने को लेकर महीनों तक अनिश्चितता बनी रही। वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले 48 देशों में से एक-चौथाई से ज्यादा देशों के प्रशंसकों को यात्रा प्रतिबंधों, कड़ी पारबंदियों या वीजा रिजेक्शन की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी यूरोपीय देश को इस तरह की पारबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके बजाय, 42 देशों को अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम का फायदा मिलता है, जिसमें अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन (ESTA) के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।

खेल में नस्लवाद

सोमाली रेफरी उमर अब्देलकादिर अर्टन से जुड़ा विवाद इस बुराई का एक बड़ा उदाहरण बन गया। अर्टन, जो अफ्रीका के सबसे सम्मानित रेफरियों में से एक हैं, को टूर्नामेंट से जुड़े होने के बावजूद आयोजन स्थल घुसने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका सोमालिया में अल-शबाब संगठन के खिलाफ हवाई हमलों का एक गुप्त और तेजी से बढ़ता हुआ सैन्य अभियान चला रहा है, जो उस देश की अमेरिका-समर्थक संघीय सरकार से लड़ रहा है। ईरान के फुटबॉल टीम के सदस्यों और सख्त अप्रवासन जांच वाले देशों के समर्थकों पर वीजा पारबंदियों को लेकर भी ऐसी ही चिंताएं सामने आईं। फीफा के नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी भाग लेने वाली टीमों को मैच से एक दिन पहले मैच वाली जगह पर पहुंचना होगा ताकि वे जरूरी स्टेडियम ट्रेनिंग और मैच से पहले की प्रेस वार्ता कर सकें। फिर भी, ईरानी टीम और उसके तुरंत साथ रहने वाले सपोर्ट स्टाफ को अमेरिका में एक रात भी रुकने की इजाजत नहीं दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान को टक्सन, एरिजोना में अपने मूल अमेरिकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग बेस को छोड़ना पड़ा और तिजुआना, मैक्सिको में कैंप लगाना पड़ा। ईरान के फुटबॉल संघ ने उत्तरी अमेरिका में अपनी टीम पर लगाई गई सख्त यात्रा पारबंदियों के बारे में फीफा से औपचारिक शिकायत की है। अमेरिकी अधिकारियों ने टीम के लिए शर्त रखी कि वे मैच से सिर्फ एक दिन पहले ही मेजबान शहरों में आएं और मैच के तुरंत बाद चले जायें, जिसकी टीम मैनेजमेंट ने कड़ी आलोचना की। इन परिवहन व्यवस्था संबंधी पारबंदियों ने टीम की तैयारी के शेड्यूल को बिगाड़ दिया, जिससे ईरानियों को अनुचित व्यवहार का आरोप लगाना पड़ा। फिर से, क्यों? क्योंकि अमेरिका के साम्राज्यवादी शासक ईरान की सरकार के साथ टकराव की स्थिति में हैं।

फीफा और अमेरिका का दोहरा मापदंड

यह विडंबना इसलिए भी चौंकाने वाली है, क्योंकि मेजबान अमेरिका खुद को खुलेपन और लोकतंत्र का चौंपियन बताता है। अमेरिका ने रूस के वर्ल्ड कप, चीन के ओलंपिक्स और कतर के वर्ल्ड कप की आलोचना की थी कि उन्होंने आजादी पर रोक लगाई और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का राजनीतिकरण किया। अब फीफा वर्ल्ड कप एक साफ दोहरे मापदंड को उजागर करता है। 2022 में, फीफा अधिकारियों ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण रूस को सभी आधिकारिक फीफा और यूईएफए नेशंस लीग अंतरराष्ट्रीय और क्लब प्रतियोगिताओं, जिसमें वर्ल्ड कप और यूरोपीय क्वालीफायर

शामिल हैं, से तुरंत और अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि फिलिस्तीनियों के भयानक व जारी नरसंहार और लेबनान पर हमले के लिए इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के बावजूद, फीफा ने उसे हल्की-फुल्की फटकार भी नहीं लगायी है। इसके बजाय, फीफा का कहना है कि इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थिति “अच्छी” है।

अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है अमेरिका

अमेरिका वर्ल्ड कप का इस्तेमाल खुलेपन, विविधता और लोकतांत्रिक जीवंतता की छवि दिखाने के लिए कर रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब शांति और खेल पसंद करने वाले दुनियाभर के लोग पेंटागन के शासकों को युद्ध भड़काने वाले, हमलावर और बंदूक की नोक पर दूसरों को झुकाने वाले के तौर पर देखते हैं। वे उन देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, जो उनके आदेश नहीं मानते और खुद अपने देश में जनविरोधी फैसलों की वजह से भारी उथल-पुथल से रूबरू हैं। ‘नो किंग्स’ (राजशाही नहीं चाहिए) आंदोलन, जन विश्वाोध का एक विकेंद्रीकृत गठबंधन है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों व उनके दूसरे कार्यकाल में कार्यकारी अधिकारों के दुरुपयोग का विरोध कर रहा है। इस आंदोलन में देशभर में हजारों जगहों पर लाखों प्रदर्शनकारी शामिल हुए हैं।

कौन है फुटबॉल का मालिक?

इसलिए यह सवाल उठता है कि फुटबॉल का मालिक कौन है? क्या यह संचालक मंडलों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मीडिया समूहों और सरकारी अधिकारियों की जागीर है? या यह उन खिलाड़ियों, खेल-प्रेमियों, समर्थकों और समुदायों की, जिनकी मेहनत और जुनून ने इसे एक वैश्विक परिघटना बना दिया?

2026 का वर्ल्ड कप इस सवाल का जवाब नहीं देता। यह बस यह दिखाता है कि फुटबॉल किस हद तक उस सत्ता-तंत्र से जुड़ गया है, जो आज के समाज को आकार देता है। वैश्विक एकता के लिए समर्पित एक टूर्नामेंट ने असमान विचलता को उजागर किया है। विविधता के जश्न ने सीमाओं के बने रहने को दिखाया है। मजदूर वर्ग के समुदायों द्वारा बनाया गया खेल अब व्यावसायिक घरानों के मुनाफे का जरिया बन गया है। और एक ऐसा आयोजन, जिसे गैर-राजनीतिक माना जाता था, वह सत्ता से अटूट रूप से जुड़ गया है।

इसका सबक फुटबॉल से कहीं आगे जाता है। खुलेपन और समावेश की भाषा के पीछे सीमाओं, पदानुक्रमों और बहिष्करणों की एक ऐसी व्यवस्था है, जो यह तय करती है कि कौन भाग ले सकता है और कौन बाहर रहता है। फुटबॉल ने बिना सीमाओं वाली दुनिया का वादा किया था। 2026 के वर्ल्ड कप ने हमें याद दिलाया है कि सीमाएं अभी भी मौजूद हैं और सत्ता ही यह तय करती है कि उन्हें कौन पार कर सकता है।

वर्गीय दृष्टिकोण

आखिरकार, वर्ग-आधारित समाज में हर संस्था-शिक्षा, संस्कृति, कानून, मीडिया, धर्म और खेल सहित-शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों की सत्ता को वैध बनाने और बनाये रखने का काम करती है। इन संस्थाओं की भूमिका, जिसमें अरबों डॉलर की फीफा भी शामिल है, यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक और राजनीतिक यथास्थिति को कोई चुनौती न दे। ये संस्थाएं कानूनी व्यवस्था, पुलिस और सेना, जिसमें आईसीई एजेंट भी शामिल हैं, का वफादारी से बचाव करती हैं। ये एजेंट सीधे तौर पर शासक बुर्जुआ वर्ग के हितों को लागू करते हैं और असहमति को दबाते हैं।

विश्वविद्यालयों के दस्तावेजों से...

(पृष्ठ 1 का शेष)

विज्ञान की पुस्तकों में भी अनेक खोजें और सिद्धांत विदेशी वैज्ञानिकों ने दिये हुए हैं। ज्ञान-विज्ञान के अनेक सिद्धांत विदेशी विचारकों ने विकसित किये हैं या उन्हें समृद्ध किया है। क्या केवल इस आधार पर उन्हें भी छोड़ दिया जाना चाहिए? अगर ऐसा किया गया, तो भारत विश्व के साझे ज्ञान-भंडार से स्वयं को अलग कर लेगा और पीछे रह जाएगा। पत्रकारों के सवालों के जवाब में कुलपति चाहे जो भी कहें, लेकिन इस पूरे अभियान के पीछे एक अलग मंसूबा काम करता दिखाई देता है। लेख के अनुसार, इसके पीछे आरएसएस से प्रभावित संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की भूमिका है, जिसकी स्थापना दीनानाथ बत्रा ने की थी।

न्यास के केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य एम. एल. गुप्ता का कहना है कि उनका संगठन लंबे समय से इंडिया नाम को बदलकर भारत करने का अभियान चला रहा है। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति या किसी देश के दो नाम नहीं हो सकते।

लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है?

हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के 108 नाम बताये जाते हैं और भक्त उन सभी नामों का स्मरण करते हैं। तो क्या आरएसएस उन नामों में भी कटौती करेगा?

एम. एल. गुप्ता का एक और तर्क है कि ब्रिटिश शासकों ने ‘इंडस’ शब्द से ‘इंडिया’ नाम दिया था और यह एक अपमानजनक नाम है। अपनी पुस्तक ‘इंडिया नहीं भारत’ में वे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग 17 विश्वविद्यालयों से इंडिया शब्द हटाया जा चुका है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी तर्क है कि ‘भारत’ एक प्रॉपर नाउन (व्यक्तिवाचक संज्ञा) है, जिसका अनुवाद नहीं हो सकता। इसलिए लिखते और बोलते समय ‘भारत’ शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनके बयान से यह समझना कठिन नहीं है कि वे ‘इंडिया’ को भारत का अंग्रेजी अनुवाद मानते हैं।

लेकिन अगर वे व्याकरण के साथ-साथ भारत के इतिहास का भी अध्ययन करते, तो संभवतः यह गलती न करते। तब वे जानते कि ‘इंडिया’ न तो भारत का अंग्रेजी अनुवाद है और न ही अंग्रेजों द्वारा दिया गया कोई औपनिवेशिक नाम।

इतिहास बताता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में फारस के सम्राट दारायुस प्रथम के अभिलेखों में सिंधु घाटी को ‘हिंदू’ या ‘हिंदुस’ कहा गया है। इसी फारसी शब्द के आधार पर यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने

‘इंडिके’ शब्द का इस्तेमाल किया और बाद के यूनानी लेखकों ने ‘इंडिका’ तथा ‘इंडिया’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

सिंधु से निकले ‘हिंदुस’ या ‘इंदोस’ शब्द के साथ फारसी भू-सूचक प्रत्यय ‘स्तान’ (जैसे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान) जुड़कर ‘हिंदुस्तान’ बना, जबकि यूनानी-रोमन परंपरा के भू-सूचक प्रत्यय ‘इया’ (जैसे सीरिया, सर्बिया) के जुड़ने से ‘इंडिया’ शब्द बना।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बात तो दूर रही, जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भी भारत में कदम नहीं रखा था, उससे बहुत पहले ही पूरी दुनिया में ‘इंडिया’ नाम प्रचलित हो चुका था।

क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज का इतिहास सभी जानते हैं। लेकिन वे अमेरिका की खोज करने नहीं निकले थे। वर्ष 1492 में वे समुद्री मार्ग से ‘इंडिया’ पहुंचने का रास्ता खोजते हुए अमेरिका पहुंच गए थे।

‘भारत’ और ‘इंडिया’, दोनों नाम सदियों से साथ-साथ प्रचलित रहे हैं। ‘इंडिया’ को पूरी तरह छोड़कर केवल ‘भारत’ को स्वीकार करने की सोच एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है।

संविधान निर्माताओं में ऐसी संकीर्णता नहीं थी। इसलिए उन्होंने संविधान की शुरुआत ही इन शब्दों से की : "India, that is Bharat..." “इंडिया अर्थात् भारत...”

उन्हें दोनों नामों को साथ लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

तो क्या आरएसएस अब संविधान में भी ‘इंडिया’ शब्द बदलना चाहता है? औपनिवेशिक शासन के विरोध का दावा करने वाले आरएसएस का वास्तविक चरित्र आजादी आंदोलन के दौरान उसकी भूमिका से स्पष्ट हो जाता है, जो विश्वासघातपूर्ण है।

सवाल यह है कि क्या आज देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण काम केवल नाम बदलना है? नाम बदलने की इस प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से धन की बर्बादी होगी। साथ ही, लोगों का ध्यान बेवजह के विवादों में उलझाया जाएगा। इससे समाज या देश का कोई वास्तविक भला होने वाला नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य देश की मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना है। इसके अलावा, इस बदलाव की कोई व्यावहारिक आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान होते हैं, जो स्वतंत्र चिंतन, उदार विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के वाहक होने चाहिए। अगर उन्हीं संस्थानों के अधिकारी बिना ठोस तर्क के इस प्रकार के निर्णय लेते हैं और देशभक्ति दिखाने के नाम पर इतिहास को ही बदलने या उलटने का प्रयास करते हैं, तो यह एक अत्यंत चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत है।

○

बिजली वितरण को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने का विरोध

गुरुग्राम (हरियाणा) : ऑल इण्डिया इलैक्ट्रिसिटी कंजुमर एसोसिएशन से संबद्ध बिजली उपभोक्ता मंच, हरियाणा ने हाल ही में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप द्वारा हरियाणा के गुडगांव व जुंह जिलों के बिजली वितरण क्षेत्र को हासिल करने संबंधी लाइसेंस के लिए हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को किये आवेदन को तुरंत प्रभाव से खारिज करने की मांग की।

मंच के राज्य सचिव मेहर सिंह बांगड़ व राज्य प्रधान इन्द्र सिंह मलिक ने 12 जून को जारी संयुक्त बयान में कहा कि यह पिछले दरवाजे से तमाम बिजली वितरण क्षेत्र को प्राइवेट कम्पनियों के हवाले करने की तैयारी है। बिजली निजी कम्पनियों के कब्जे में जाने के बाद लगातार महंगी होने से आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जायेगी। बिजली जीवन की मूलभूत जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि बिजली की दरें आम

आदमी की पहुंच के अंदर रहें। यह जग जाहिर है कि प्राइवेट कम्पनियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। इससे बिजली लगातार महंगी होने से पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं पर और अधिक मार पड़ेगी। बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ बिजली कर्मचारियों की नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। यह भी गौरतलब है कि डीएच बीवीएन का तकरीबन 70% रैवन्यू अकेले गुडगांव जिले से आता है। इसके प्राइवेट कंपनी के पास जाने से सरकारी नियंत्रण वाले बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति गंभीर खतरे में पड़ जाएगी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं पर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिजली उपभोक्ता मंच इसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं व बिजली कर्मचारियों की यूनियनों से भी इसका कड़ा विरोध करने का आह्वान किया।

कॉमरेड रबिन समाजपति स्मृति सभा आयोजित

रांची, झारखण्ड।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य एवं झारखंड राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति की स्मृति सभा पार्टी की झारखण्ड राज्य सांगठनिक कमेटी के तत्वावधान में 12 जुलाई को रांची के सेक्टर-2 स्थित बंगीय सांस्कृतिक परिषद सभागार में आयोजित की गई। सभा में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक तथा विभिन्न वामपंथी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता झारखंड राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉमरेड आर. एस. शर्मा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं बिहार राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने संबोधित किया। इसके अतिरिक्त सीपीआई (एम) की राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड सुखनाथ लोहरा तथा सीपीआई (एमएल) के झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड मनोज भक्त ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

मुख्य वक्ता कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य के गठन के बाद जब पार्टी संगठन अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब कॉमरेड रबिन समाजपति ने अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद संगठन बनाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उनके अथक प्रयासों से झारखंड में पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत हुआ, बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता-समर्थक पार्टी से जुड़े तथा विभिन्न जनसंगठनों की गतिविधियां राज्य के विस्तृत क्षेत्रों तक फैल सकीं।

उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, जनविरोधी नीतियों, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमलों, मजदूरों, किसानों एवं अन्य तबकों के मेहनतकशों की जायज मांगों तथा सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर झारखंड में संचालित अनेक जनआंदोलनों में कॉमरेड रबिन समाजपति ने अग्रणी भूमिका निभायी। रांची के गरीब बस्तीवासियों को उजाड़ने के विरुद्ध उनके नेतृत्व में गठित 'बस्ती बचाओ संघर्ष समिति' ने लंबे समय तक



संघर्ष का नेतृत्व किया। जनता के संगठित आंदोलन के दबाव में प्रशासन को कई बार पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा तथा 'पुनर्वास से पहले बेदखली नहीं' के नारे को जनआंदोलन के केन्द्रीय नारे के रूप में स्थापित किया जा सका।

अपने संबोधन में वक्ताओं ने झारखंड में डोमिसाइल विवाद के दौरान कॉमरेड रबीन समाजपति की दूरदर्शी भूमिका को भी श्रद्धापूर्वक याद किया। वक्ताओं ने कहा कि सांप्रदायिकता और फूटपरस्त राजनीति के विरुद्ध वर्गीय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा जनता के व्यापक हितों को केन्द्र में रखकर उन्होंने पूरे राज्य में व्यापक प्रचार अभियान चलाया।

डोमिसाइल के प्रश्न पर पार्टी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, जिसने लोगों की भ्रांतियां दूर करने और सही जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अंत में 'इंटरनेशनल' के समूह गान के साथ सभा का समापन हुआ।

सूचना

एसयूसीआई (सी) की केन्द्रीय कमेटी ने केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड स्वपन चटर्जी को झारखण्ड राज्य सांगठनिक कमेटी का सचिव मनोनीत किया है।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने के खिलाफ हुए आंदोलन की जीत

जून की शुरुआत में भोपाल (मध्य प्रदेश) के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। इसमें विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय' करने की बात कही गई थी। वाग्देवी ज्ञान की हिंदू देवी को कहा जाता है, जबकि 'भोजपाल' परमार राजवंश के राजा भोज के सम्मान में जोड़ा गया था। इस फैसले से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विरोध करने वालों का कहना था कि नाम बदलने से महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतउल्ला भोपाली की विरासत मिट जाएगी, जिनके नाम पर 1988 में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। इसे लेकर

छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और जाने-माने शिक्षाविदों में भारी नाराजगी थी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपे गए एक ज्ञापन में 1,000 से अधिक नागरिकों, शिक्षाविदों और छात्रों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भोपाल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ वे नागरिक कर्तव्यबोध, ऐतिहासिक जिम्मेदारी के एहसास और गहरे दुख के साथ यह पत्र भेज रहे हैं। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतउल्ला भोपाली (1864-1926) जैसी बड़ी हस्ती का अपमान करने के तुल्य होगा। इसलिए उन्होंने माननीय राज्यपाल से अपील की कि वे अपने संवैधानिक

अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज करें और इस राष्ट्रीय नायक की यादों को संजोये रखें।

उन्होंने आगे लिखा कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम मिटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सामूहिक विरासत को मिटाने जैसा है। मौलाना बरकतउल्ला भोपाली सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक वैश्विक राजदूत थे। उन्होंने अमेरिका, जापान और यूरोप में रहकर काम किया, गदर पार्टी की स्थापना में मदद की और 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप को लेकर बनी भारत की पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे।

पिछले पांच दशकों से यह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में इसी नाम से पहचाना जाता है। नाम बदलने से न केवल प्रशासनिक उलझनें पैदा होंगी और विश्वविद्यालय की साख पर असर पड़ेगा, बल्कि यह इतिहास को बदलने की एक गलत परंपरा की शुरुआत भी होगी। हम मौलाना बरकतउल्ला को उनका जीवन वापस नहीं दे सकते, न ही इस सच को बदल सकते हैं कि उन्होंने अपने देश को आजाद देखने की हसरत लिए परदेस में ही आखिरी सांस ली। एक आभारी देश होने के नाते हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों में उनकी यादों को जिंदा रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें।

साम्राज्यवाद और फासीवाद के खिलाफ दुनियाभर के मेहनतकशों की मजबूत एकता आज की सबसे बड़ी जरूरत — कॉमरेड अरुण कुमार सिंह



काठमांडू, नेपाल : 21 जुलाई को काठमांडू में आईसीओआरसी की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसयूसीआई (सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जब तक साम्राज्यवाद है, दुनिया में युद्ध का खतरा बना रहेगा। चूंकि साम्राज्यवाद दुनिया में हो रहे युद्धों की जड़ है, इसलिए पक्की शांति कायम करने के लिए साम्राज्यवादी व्यवस्था का खात्मा होना जरूरी है।

कॉमरेड सिंह ने कहा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया में शांति आने के किये गये दावे के बावजूद अब दुनिया पर युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दुनियाभर के मेहनतकशों को अपने-अपने देशों की सरकारों पर दबाव बनाकर युद्ध और साम्राज्यवादियों की दखलअंदाजी का विरोध करना चाहिए। दुनिया के विभिन्न देशों में फासीवादी रुझान बढ़ रहे हैं। नेपाल और भारत के ऐतिहासिक और पारिवारिक रिश्ते की याद दिलाते हुए कॉमरेड सिंह ने कहा कि भारत

के आजादी आंदोलन में नेपाल ने अहम भूमिका निभायी थी। भारत को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दक्षिण एशिया में साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, फूटपरस्त और साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजदूर वर्ग का एक साझा संघर्ष जरूरी है। उन्होंने मजदूर-किसानों और छात्र-नौजवानों के बीच वैचारिक-सांस्कृतिक लेन-देन बढ़ाकर एशियाई स्तर पर एकता कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। मार्क्स-एंगेल्स के नारे "दुनिया के मजदूरों, एक हो" याद करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है।

उन्होंने यह यकीन जताया कि भले ही समाजवादी देश कमजोर हों, लेकिन मजदूर आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और आखिर में समाजवाद का भविष्य पक्का करेगा। उन्होंने दावा किया कि दुनियाभर के मजदूरों के संयुक्त संघर्ष से ही सामाजिक बदलाव मुमकिन होगा। उन्होंने एशियाई देशों में मजदूरों, किसानों, छात्रों और युवाओं की एकता को मजबूत करने और साम्राज्यवाद व फासीवाद के खिलाफ एक साझी मुहिम को आगे बढ़ाने का भी वादा किया।

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे, एनटीए भंग करने और परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर और जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के समर्थन में 18 जुलाई को

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन हटाने और विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की एआईडीएसओ ने की कड़ी निंदा

एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने 18 जुलाई को जारी प्रेस बयान में कहा:

"पिछले एक महीने से अधिक समय से देश के छात्र, युवा, अभिभावक और आम लोग पेपर लीक और एनटीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से जवाबदेही, धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए को तुरंत भंग करने की मांग हम सभी कर रहे हैं। उपरोक्त मांगों को लेकर सोनम वांगचुक और कई अन्य छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल इस देश के छात्रों, अभिभावकों और सभी शिक्षा-प्रेमी लोगों के बीच बढ़ते आक्रोश की अभिव्यक्ति है।

पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और अन्य छात्रों का गिरता स्वास्थ्य देश के सभी विवेकशील नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है।



जयपुर



जंतर मंतर

लूनियावास, जयपुर में एआईडीवाई और दिल्ली जंतर मंतर पर एआईडीएसओ ने किया प्रदर्शन